



प्रेस विज्ञप्ति

30.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के खूंटी ज़िले में मनरेगा सहित विभिन्न विकास योजनाओं से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर हुए गबन के मामले में, पांच नए आरोपियों—**श्रीमती अमिता झा** (आरोपित संख्या 9), **सिद्धार्थ सिंघल** (आरोपित संख्या 10), **मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी** (आरोपित संख्या 11), **पवन कुमार सिंह** (आरोपित संख्या 12), और **श्रीमती कमलेश सिंघल** (आरोपित संख्या 13)—के खिलाफ, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष चौथी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इस शिकायत के माध्यम से, माननीय विशेष न्यायालय से विशेष रूप से यह प्रार्थना की गई है कि रांची के मौज़ा: बोरिया में स्थित 17 डेसिमल ज़मीन को ज़ब्त किया जाए; यह ज़मीन अपराध से अर्जित आय (पीओसी) के रूप में प्राप्त 1.33 करोड़ रुपये से खरीदी गई थी।

ईडी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो द्वारा सेवारत सरकारी अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता **राम बिनोद प्रसाद सिन्हा** भी शामिल थे, के खिलाफ दर्ज की गई 16 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 2009-2011 के दौरान खूंटी जिले में विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें से 18.06 करोड़ रुपये फर्जी और बेहद घटिया तरीके से काम करवाकर गबन कर लिए गए। जांच में यह भी साबित हुआ कि तत्कालीन उपायुक्त, खूंटी, **श्रीमती पूजा सिंघल (आईएस)** इस आपराधिक साजिश की मुख्य लाभार्थी थीं; उन्होंने परियोजनाओं को मंजूरी देने के बदले जारी किए गए परियोजना धनराशि का 5% नकद कमीशन के रूप में व्यवस्थित तरीके से वसूला और दोषी अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई से सक्रिय रूप से बचाया। अपराध से प्राप्त आय को बाद में बेनामी संस्थाओं, पारिवारिक प्रतिनिधियों और कॉर्पोरेट ढांचों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से फिर से निवेश किया गया। जांच के शुरुआती चरणों में, आठ आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दायर की गई थीं, जिनमें पूजा सिंघल, उनके पति **अभिषेक झा**, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय प्रबंधक **सुमन कुमार**, और **मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड** शामिल थे।

जांच से अब पता चला है कि पांच नए आरोपितों ने अपराध की इन आय को परत-दर-परत बिछाने और एकीकृत करने में सक्रिय रूप से मदद की। **श्रीमती अमिता झा** (62 वर्ष, सह-आरोपित अभिषेक झा की मां) ने अपराध की आय को, जिसमें 20.70 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जमा शामिल थी, अपने बैंक खातों



के माध्यम से भेजने की अनुमति दी, जिसे बाद में मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में शेयर पूंजी के रूप में पेश किया गया। उन्होंने पल्स सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, बरियातू रोड, रांची के परिसर में 1.65 डेसिमल का एक प्रमुख कोने का भूखंड भी अर्जित किया, जिसे सीधे अपराध की आय से वित्त पोषित किया गया था। **सिद्धार्थ सिंघल** (43 वर्ष, पूजा सिंघल के भाई) ने मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में शेयर कैपिटल के तौर पर बिना हिसाब का की नकदी निवेश की। तलाशी अभियान के दौरान ज़ब्त किए गए उनके मोबाइल फ़ोन के डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस से उनके और सह-आरोपित सीए सुमन कुमार के बीच व्हाट्सएप बातचीत का पता चला, जिससे पता चला कि मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी को शामिल किया गया था और बोरिया में 17 डेसिमल ज़मीन पूजा सिंघल के कहने पर और उनके फ़ायदे के लिए ली गई थी। **पवन कुमार सिंह** (45 वर्ष, को-आरोपित सीए सुमन कुमार के भाई) और **श्रीमती कमलेश सिंघल** (75 वर्ष, पूजा सिंघल की माँ) को **मेसर्स राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी** का पदनामित हिस्सेदार बनाया गया था, जो उस एलएलपी और उसकी संपत्तियों पर पूजा सिंघल के फायदेमंद मालिकाना हक को छिपाने के लिए बेनामी अगुआ के तौर पर काम कर रहे थे। उक्त एलएलपी के माध्यम से, 1.33 करोड़ रुपये की नकद राशि— जो 'अपराध से प्राप्त आय' (पीओसी) का हिस्सा थी—का भुगतान रांची के मौजा: बोरिया में 17 डेसिमल ज़मीन खरीदने के लिए किया गया; इस प्रकार, इन 'दागदार निधियों' का अचल संपत्ति में एकीकरण पूरा हो गया।

जांच के दौरान, 06.05.2022 को पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के 24 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इसके परिणामस्वरूप, रांची में सह-आरोपी सीए सुमन कुमार के आवास से लगभग 17.49 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद और ज़ब्त की गई, और एक सहयोगी के ठिकाने से 1.82 करोड़ रुपये ज़ब्त किए गए; जिससे इस मामले में ज़ब्त की गई कुल नकदी लगभग 19.31 करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा, अपराध-संकेती दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, शेयर प्रमाण पत्र, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण सबूतों वाले डिजिटल उपकरण भी ज़ब्त किए गए। ईडी ने चार 'अनंतिम कुर्की आदेशों' के तहत आरोपितों की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी पुष्टि विद्वान निर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा की गई है।

आगे की जांच जारी है।